

क्रांति सामाज्य

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार, 05 अक्टूबर-2021 वर्ष-4, अंक-254 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com f www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वायु प्रदूषण प्रबंधन पर काय करने के लिए दिल्ली को एनसीएपी के तहत मिलेगा 'ग्रीन फंड'



नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण प्रबंधन में कुछ विशेष कमियों को दूर करने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 18 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। हालांकि, दिल्ली को एनसीएपी के तहत ये रकम पहली बार मिल रही है।

2019 में शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली को धन प्राप्त होगा। एनसीएपी, 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। इसके लिए आधार वर्ष 2017 रखा गया है।

2019 के बाद से प्रदूषण प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के 18.74 करोड़ रुपये एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली को एनसीएपी के तहत 18.74 करोड़ रुपये मिलेंगे। एनसीएपी उन 132 शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करते हैं। इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर की गई है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी को दो साल के लिए एनसीएपी के तहत कोई धन नहीं मिला क्योंकि उसके पास अन्य संसाधन के रूप में 2 हजार सीसी से ऊपर के ग्रीनलैंड वाहनों पर लगाया जाने वाला जीन सेंसर, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा किया जाता है और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन पर लगाने वाला प्रदूषण कर उपलब्ध थे।

लखीमपुर खीरी कांड

यूपी पुलिस पर गरजीं प्रियंका गांधी, कहा- छू कर देखो मुझे... अपने अफसरों-मंत्रियों से जाकर वारंट लाओ

नई दिल्ली। किसानों की हत्या के बाद लखीमपुर खीरी जा रही प्रियंका पुलिस का दम फूल गया। चप्पे-चप्पे पर नाकाबंदी, हर रास्ते पर बड़े-बड़े अधिकारियों की तेनाती के बाद भी प्रियंका गांधी प्रशासन को चकमा देते हुए आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही प्रशासन को पता चलता कि प्रियंका ने रास्ता बदल दिया है, अधिकारियों के हाथ-पांव फूल जाते। उन्हें हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस को रातभर मशकत करनी पड़ी। इस बीच उनके साथ काफी धक्का-मुक्की भी की गई। प्रियंका का आरोप है कि उन्हें घसीटा व धकेला भी गया। इस बीच उनकी पुलिस के अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई, जिसमें प्रियंका गांधी यूपी पुलिस के अधिकारियों को कानून का पाठ सिखाते हुए देख रही हैं। प्रियंका के सवालों और गुस्से के आगे यूपी पुलिस के अधिकारी चुपपी साधे हुए हैं।

ये लीगल स्टेटस है तुम्हारा एक वीडियो में प्रियंका यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रही हैं। वह कहती हैं- %इसमें बिठल कर मुझे तुम मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा। मत समझो कि मैं कुछ नहीं समझती... अरेस्ट करो खुशी से जाउंगी मैं। ये जो जबरजस्ती घेर रहे हो, डकैल रहे हो न... इसमें फिजिकल असाइल्ट, अटेम्प्ट टू किडनेप, किडनेप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट... समझते हो न। छू कर देखो मुझे, जाकर अपने अफसरों से अपने मंत्रियों से जाकर वारंट लाओ। महिलाओं को आगे मत करो, महिलाओं से बात करना सीखो। तुम्हारे यहां कानून नहीं होगा... इस देश में कानून है। तुम मुझे घसीट कर डकैल कर यहां लाए हो। कोई हक नहीं है तुम्हें, कोई हक नहीं है। मैं उन लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट



नहीं हूँ। प्रियंका गांधी बाड़ा का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस की कुछ महिला अधिकारी दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ उनकी तीखी बहस हो रही है। वीडियो में प्रियंका कहती हुई देख रही हैं- ये धाराएं सब पर लागेंगी, सबके नाम के साथ लागेंगी। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, जिन लोगों को तुमने मारा है... समझो।

अधिकारियों के हाथ-पांव फूल जाते। उन्हें हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस को रातभर मशकत करनी पड़ी। इस बीच उनके साथ काफी धक्का-मुक्की भी की गई। प्रियंका का आरोप है कि उन्हें घसीटा व धकेला भी गया। इस बीच उनकी पुलिस के अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई, जिसमें प्रियंका गांधी यूपी पुलिस के अधिकारियों को कानून का पाठ सिखाते हुए देख रही हैं।

प्रियंका गांधी को रिहा करने को लेकर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता-कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को हर्षाव इलाके से पकड़े जाने के बाद पीएसी की सेंकेड वाहिनी में लाकर रखा गया है। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर धरने पर बैठ कर प्रदर्शन किया। काफी देर तक धरने पर बैठे रहने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब हंगामा शुरू कर दिया है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने बाहर लगे गेट को तोड़ने का प्रयास किया, जिसपर पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इस को लेकर मामला तूल पकड़ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को रिहा करने को लेकर पुलिस से भिड़ गए। धक्का-मुक्की की। कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है।

बुजुर्गों के लिए जारी सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर आए 3.39 लाख से अधिक फोन

नई दिल्ली। बुजुर्गों के लिए सरकारी हेल्पलाइन सुविधा 'एल्डरलाइन' पर मई माह से 3.39 लाख से अधिक फोन आए हैं। इनमें से 79 हजार से अधिक फोन उत्तर प्रदेश से किए गए हैं। 'टाटा टूरस्ट' के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन सुविधा का लक्ष्य बुजुर्गों को सहायता मुहैया कराना है। 'एल्डरलाइन' के जरिये महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने जांगी मदद मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 54,432 कॉल उत्तराखंड, 42,610 तेलंगाना, 27,708 तमिलनाडु और 22,711 कर्नाटक से किए गए। 'एल्डरलाइन' के जरिये महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने अधिक मदद मांगी है। आंकड़ों के अनुसार 23,390 पुरुषों और 8,178 महिलाओं ने इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया।

सहायता (13,496), पेंशन (8,952), दुर्व्यवहार (1890), स्वास्थ्य संबंधी सहायता (1202), बचाव (423) और वृद्धाश्रमों से संबंधित प्रश्न (632) शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन पर किए जाने वाले कॉल की मदद से सरकार को बुजुर्गों के लिए नीति निर्माण की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक मई से 3,39,879 कॉल मिले थे, जिनमें से 3,02,195 कॉल ऐसे थे, जो सेवा योग्य नहीं थीं, जैसे कि इन कॉल के जरिये जिन लोगों ने मदद मांगी, वे बुजुर्ग नहीं थे। जो 37,684 वास्तविक कॉल आए, उनमें से 17,933 कॉल (47.59 प्रतिशत) कोविड-19 संबंधी सहायता, टीकाकरण की जानकारी से संबंधित थे।

बिहार, झारखंड, बंगाल के कई हिस्सों में 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावना

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी की संभावना है। हालांकि, 6 अक्टूबर तक पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की भी संभावना है। एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इससे बनने वाले चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षीमण्डल स्तर तक फैला हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और कम चिह्नित होने की संभावना है।

कहा गया है कि चार अक्टूबर को बिहार में और झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

कर्नाटक तट से पूर्व मध्य अरब सागर तक चल रही है, जो निचले क्षीमण्डल स्तर में केरल तट से दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण में है। अगले 2-3 दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से 6 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर तक दक्षिण कोकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि इसके प्रभाव में अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व मध्य और उससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

पति पत्नी साथ नहीं रह सकते तो एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर

नई दिल्ली। वर्ष 1995 में शादी के बाद महज पांच छह दिन तक साथ रहने वाले एक दंपती ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप एक साथ नहीं रह सकते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस बोपन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट के तलाक के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी से कहा कि आपको व्यवहारिक होना चाहिए, पूरी जिंदगी अदालत में एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं बिताई जा सकती। आपकी उम्र 50 साल और पति 55 साल के हैं। पीठ ने दंपती को स्थायी गुजारा भत्ता पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए कहा और

दिसंबर में याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है। पत्नी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा तलाक को मंजूरी देना गलत था। हाईकोर्ट ने कहा कि आपका व्यवहारिक होना चाहिए, पूरी जिंदगी अदालत में एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं बिताई जा सकती। आपकी उम्र 50 साल और पति 55 साल के हैं। पीठ ने दंपती को स्थायी गुजारा भत्ता पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए कहा और

दूट के आधार पर तलाक की अनुमति देना बिल्कुल सही था। वकील ने कहा कि पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और वह स्थायी गुजारा भत्ता देने को तैयार है। पति ने दावा किया कि 13 जुलाई, 1995 को शादी के बाद उच्च शिक्षित और संपन्न परिवार से आने वाली उनकी पत्नी ने उन पर अपनी बूढ़ी मां और बेरोजगार भाई को छोड़ अगस्तला स्थित अपने घर में 'घर जमाई' बनकर रहने के लिए दबाव डाला। पत्नी के पिता आईएसए अधिकारी थे। पति ने मामले को शांत करने की हसंभव कोशिश की लेकिन पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गईं। तब से दोनों अलग रह रहे हैं।

44 करोड़ बच्चों को दिया जाना है टीका, बीमार को पहले, स्वस्थ की बारी बाद में

नई दिल्ली। देश में बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण में ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो किन्हीं अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने बताया कि यह बच्चे चाहे किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, उन्हें तुरंत कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिलवाना जरूरी है। इन बच्चों के बाद बाकी स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण होगा। डॉ. अरोड़ा ने बताया, इन हाई-रिस्क बच्चों की पहचान के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा गया है जिनके संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की आशंका है। इसके लिए अगले दो हफ्ते में प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों व वयस्कों के लिए डीएनए आधारित जायडस कैडिला टीके के आपात उपयोग की अनुमति दी थी। इसे लेकर सरकार व कंपनी में बातचीत हो रही है और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपलब्ध करवाने का इंतजार हो रहा है। टीके के संयुक्त परीक्षण में डब्ल्यूएचओ व एम्स को इस टीके की

वजह से 18 वर्ष से कम उम्र के समूह में सिराप्रवैलेंस 55.7 और 18 वर्ष से अधिक उम्र के समूह में 63.5 प्रतिशत मिला था। यह बिना सूई के दिया जाने वाला यह टीका अहमदाबाद में जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। 44 करोड़ बच्चों को दिया जाना है टीका-डॉ. अरोड़ा ने कहा कि बच्चे इस वायरस के रोगवाहक हो सकते हैं, वे खुद संक्रमित नहीं होते। इसलिए उनके इर्द-गिर्द रहने वाले वयस्कों का टीकाकरण बहुत जरूरी है। यह उन्हें एक सुरक्षा घेरा देता है। देश का लक्ष्य सभी वयस्कों का टीकाकरण है, जिसके बाद 18 साल से कम उम्र के करीब 44 करोड़ बच्चों का तेजी से टीकाकरण होगा। साल के आखिर तक और आगे

विश्व बैंक की सलाह-स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार जरूरी नहीं, बच्चों का विकास होता है प्रभावित

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने सलाह दी है कि देशों को स्कूल खोलने के लिए पहले व्यापक टीकाकरण किए जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण इस तर्फ स्पष्ट संकेत करते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है। विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने दुनियाभर के उन देशों के अनुभव के आधार पर एक नीतिगत नोट तैयार किया है, जहां स्कूल फिर से खोले जा चुके हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि एहतियात के साथ स्कूल खोलने से छात्रों, कर्मचारियों व समाज में संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम है। क्योंकि, महामारी की चपेट में आने के एक साल बाद, वायरस और

बीमारी दोनों के बारे में अब पर्याप्त जानकारी है, इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव को कम करने के बारे में भी पर्याप्त जानकारी है। ऐसे में स्कूल बंद करना आखिरी उपायों में शामिल होना चाहिए। टीका विकसित होने से पहले फिर से स्कूल खोलने के वाले देशों के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल खोलने के लिए व्यापक टीकाकरण की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा छात्रों के स्कूल लौटने से उनका डर भी दूर होगा।

बच्चों का विकास होता है प्रभावित नोट में कहा गया है कि स्कूलों को बंद रखना बीमारी का खतरा तो घटता है, लेकिन

बच्चों की पढ़ाई, मनोसामाजिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को खतरा में डालता है। स्कूल फिर से खोलने का फैसला इन्हें खोलने और बंद रखने के बीच के नफा-नुकसान की तुलना कर लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अब तक के अनुभव से यही सामने आता है कि स्कूल बंद रखना ज्यादा नुकसानदेह है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में 80 फीसदी स्कूल चालू हैं। इनमें से 54 फीसदी में छात्र व्यक्तिगत रूप उपस्थित हो रहे हैं। 34 फीसदी मिश्रित तरीके से चल रहे हैं, जबकि 10 फीसदी सिर्फ दूरस्थ शिक्षण के लिए खुले हैं।

अरब बच्चे हो गए थे स्कूलों से दूर नोट के मुताबिक जहां सरकार व समाज डरते हैं कि स्कूलों को फिर से खोलने से संक्रमण फैल सकता है सिर्फ वहीं स्कूल बंद हैं। जबकि, स्कूलों को खोलने से जुड़े साक्ष्य इस धारणा के उलट हैं। इन देशों को स्कूल बंद रखने के नुकसानों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि स्कूल बंद रखना, स्कूल खोलने से जुड़े जोखिमों से कहीं ज्यादा है। पिछले साल कोविड के कारण 188 से अधिक देशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिससे 1.6 अरब बच्चे स्कूलों से दूर हो गए। उस समय यह ठीक था, क्योंकि तब कोई महामारी के

बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद रखे जाएं। छोटे बच्चों में संक्रमण की संभावना बेहद कम विश्व बैंक कहता है निगरानी व अध्ययन से पता चलता है कि वयस्कों और किशोरों की तुलना में, छोटे बच्चे, विशेष रूप से दस वर्ष से कम के बच्चे, संक्रमण के लिहाज से काफी कम संवेदनशील हैं। ऐसे में उनमें संक्रमण की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा अगर बच्चे संक्रमण की चपेट में आ भी जाएं, तो उनमें मृत्यु का जोखिम बहुत कम है।

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेस नोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

समस्या आपकी हमें भेजे

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखें या बताएं और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा, वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरो और अन्य शहर, ग्राम में पत्रकारों की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

संपादकीय

वैक्सीन की लड़ाई

दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर देशों के बीच उभरे विवाद बेहद दुखद और आपत्तिजनक हैं। हम भारत और इंग्लैंड के बीच वैक्सीन को लेकर जो विवाद देख रहे हैं, उससे निस्संदेह बचा जा सकता था, मगर इंग्लैंड की हठधर्मिता ने भारत को 'जैसे को तैसा' शैली में जवाब देने को मजबूर कर दिया। अब भारत से इंग्लैंड जाने वालों को जहां दस दिन के क्वारंटीन से गुजरना होगा, वहीं इंग्लैंड से भारत आने वालों को भी ऐसी ही परेशानी होगी। इंग्लैंड का यह फैसला समझ से परे दिखता है, वह भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता तो देता है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त लोगों को टीकायुक्त नहीं मानता। आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में लोगों को जो वैक्सीन दी जा रही है, उसी फॉर्मूले की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में भी लग रही है। कायदे से इंग्लैंड को भारतीय वैक्सीन और टीका प्राप्त भारतीयों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक जिन सात वैक्सीन को मंजूरी दी है, उनमें इंग्लैंड में निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा भारत में बनी कोविशील्ड को केवल एक देश में दो बार ट्रायल से गुजारा गया है। यह इंग्लैंड का अहंकार ही है कि वह भारतीय वैक्सीन या भारतीय वैक्सीन प्राप्त लोगों को तब तक नहीं देता। यहां लगे हाथ यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में दूसरे नंबर पर मान्यता प्राप्त वैक्सीन फाइजर है, जिसके लिए 100 से ज्यादा देशों ने अपने दरवाजे खोले हैं। मोदेरना के लिए 76 देश और जॉनसन के लिए 70 देश आगे आए हैं। चीन निर्मित वैक्सीन सीनोफार्म को 65 देशों की मंजूरी हासिल है और सीनोवेक को 40 देशों की। टॉप सात वैक्सीन की बात करें, तो सबसे कम ट्रायल कोविशील्ड का ही हुआ है। हमने शायद यह मान लिया था कि जब इसी फॉर्मूले की ब्रिटिश वैक्सीन का अधिकतम ट्रायल हो ही रहा है, तो हमें अलग से ट्रायल की क्या जरूरत? चूंकि हमने ट्रायल पर जोर नहीं दिया, इसलिए हमारी अपनी कोवैक्सीन को वाजिब मान्यता नहीं मिली। दुनिया के देश ट्रायल देखते हैं, जबकि हमारा ध्यान फॉर्मूला प्राप्त करने पर रहता है। नहीं भूलना चाहिए कि जहां मान्यता प्राप्त वैक्सीन वाले देशों को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, वहीं कोवैक्सीन का निर्माण ज्यादा मांग के अभाव में प्रभावित होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मांग तभी बढ़ेगी, जब हम ट्रायल या सफलता के आंकड़े सामने रखेंगे। देखा होगा कि भारत वैक्सीन निर्माण में पीछे नहीं रह जाए। भारत ही नहीं, दुनिया को अभी लंबा रास्ता तय करना है। अभी तक दुनिया में केवल 35 प्रतिशत लोगों का ही टीकाकरण पूरा हुआ है। तमाम देशों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि सब मिल-जुलकर वैक्सीन की राह पर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैक्सिग को मंजूरी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे।



आज के ट्वीट

संदेश

नशे में खोखला बॉलीवुड आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहता है?? नशे करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। ऐसे नशेड़ी लोगों का बॉयकॉट करने का समय आ गया है। इन नशेड़ी कलाकारों ने बॉलीवुड को बदनाम कर रखा है।
-- बबीता फोगाट

प्रेम

आचार्य रजनीश आशो/ प्रेम शारीरिक नहीं है, इसका नाता कहीं विश्रांति से है, पिघलने से है, पूरा मिट जाने से है। उन पलों में यह मिट जाता है अतः निश्चित ही यह शारीरिक नहीं। तुम्हें अधिक प्रेम देना सीखना होगा। तुम्हें बस लेने का अनुभव है। तो पहला अनुभव जो उसके अचेतन तक पैदा जाता है वह प्रेम लेने का है। परंतु समस्या यह है कि हर व्यक्ति बच्चा रहा है, और हर व्यक्ति के भीतर प्रेम पाने की आकांक्षा है; कोई भी किसी अलग ढंग से पैदा नहीं हुआ है। तो सभी मांग रहे हैं, 'हमें प्रेम दे' लेकिन देने वाला कोई भी नहीं क्योंकि वे भी उसी तरह पैदा हुए हैं। हमें सजग व सचेत रहना चाहिए कि हम जन्म की यह अवस्था हमारे पूरे जीवन पर आच्छादित न हो जाए। प्रेम देना बहुत सुंदर अनुभव है क्योंकि देने में तुम सम्राट हो जाते हो। लेना बहुत तुच्छ अनुभव है क्योंकि तुम भिखारी हो जाते हो। जहां तक प्रेम का प्रश्न है, भिखारी मत बनो, सम्राट रहो क्योंकि तुम्हारे भीतर यह गुणवत्ता असीम है। तुम जितना देना चाहो, दिए चले जा सकते हो। तुम चिंता मत करना कि यह चुक जाएगा, कि एक दिन तुम पाओगे कि 'हे प्रभु, मेरे पास तो प्रेम देने के लिए बचा ही नहीं।' प्रेम मात्रा नहीं, गुणवत्ता है, ऐसी गुणवत्ता है, ऐसी प्रेम है और पकड़े रहने से मर जाती है। अतः इसे पूरी तरह लुटा दो। चिंता मत लो, किसे...यह कंजूस व्यक्ति सोचता है- मैं उसे प्रेम दूंगा जिसमें अमुक गुण होंगे। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कितना प्रेम है...तुम भरे हुए बादल हो। बादल चिंता नहीं लेता कि कहां बरसे। चट्टान हो कि उपवन या कि सागर, कोई परवाह नहीं। यह स्वयं को हल्का करना चाहता है और वह निर्भरता ही विश्रांति है। तो पहला रहस्य है- इसे मांगें मत, प्रतीक्षा मत करें कि कोई आगाया तो हम देंगे। बस दे दें। अपना प्रेम किसी को भी दें...किसी अजनबी को ही सही। प्रश्न यह नहीं है कि तुम कुछ बहुत कीमती दे रहे हो, कुछ भी, थोड़ी सी सहायता, और वह काफी है। चौबीस घंटों में तुम जो भी करते हो उसे प्रेम से करो और तुम्हारे दिल की पीड़ा मिट जाएगी। और क्योंकि तुम इतने प्रेमपूर्ण होओगे, लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। यह स्वाभाविक नियम है। तुम्हें वही मिलता है जो तुम देते हो। वास्तव में तुम उससे अधिक पाते हो जो तुम देते हो। देना सीखो और पाओगे कि लोग तुम्हारे प्रति कितने प्रेमपूर्ण हैं, वही लोग जिन्होंने तुम्हारे प्रति कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी समस्या यही है कि तुम्हारा दिल प्रेम से भरा है, लेकिन तुम कंजूस रहे हो; वही प्रेम तुम्हारे दिल पर बोझ हो गया है।

मोदी की अमेरिका यात्रा पर कुतर्क गढ़ती सोशलमीडिया ?



(लेखक- प्रभुनाथ शुक्ल)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जैसे विशिष्ट गणराज्य के दौर पर हैं। वैश्विक संदर्भ के वर्तमान परिपेक्ष में भारत के लिए यह यात्रा बेहद अहम है। मोदी की इस यात्रा की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक बार फिर अतिवादी ताकतों अपना आधिपत्य स्थापित जमा लिया हो। जबकि भारत दुनिया के हर मंच से आतंकवाद की आलोचना करता रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से भारत की चुनौतियां बढ़ गई हैं, उस हालात में जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश अघोषित रूप से तालिबान के साथ खड़े हों। नेपाल और बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है। भारत कई ट्रिलियन डॉलर का निवेश अफगान में कर चुका है। उस हालात में देश के सामने सामरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे में यह यात्रा हमारे लिए विशेष हो जाती है। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप शासन का अंत हो चुका है और जोबाइडन सत्ता में हैं। भारत और अमेरिका के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद भी दक्षिण एशिया में अमेरिकी उपस्थिति के लिए दोनों राष्ट्रों को कूटनीतिक तौर पर एक दूसरे की आवश्यकता है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं अमेरिका के लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि चीन की बढ़ती चुनौतियां उसे मुश्किल में डाल रही हैं। रूस और चीन की जुगलबंदी अमेरिका के लिए घातक हो सकती है। लेकिन सोशलमीडिया पर प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा को जिस संदर्भ में लिया जा रहा है वह बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री की एक वायरल हुई तस्वीर को लेकर सत्ता और विपक्ष में शीतयुद्ध चलने लगा है। देश को इस से क्या मिलेगा यह अलग तथ्य है। लेकिन सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म पर यह

साबित करने की कोशिश की जा रही है कि %तेरे पीएम से अच्छा मेरा पीएम%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान सोशल मीडिया में जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण फाइलों को निपटते हुए देखे जा रहे हैं। फिर इस तस्वीर में आखिर बुराई क्या है जो बहस का हिस्सा बनी है। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं उस संबंध में सत्ता और विपक्ष सोशलमीडिया पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा कि अमेरिकी यात्रा से भारत को कितनी उम्मीदें हैं। भारत को इस यात्रा से क्या लाभ मिल सकता है। मोदी क्या ट्रंप जैसे बाइडन के करीब आ सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर अमेरिका क्या भारत की चिंताओं पर ख्याल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अमेरिका क्या भारत को कोई मजबूत भरोसा दे सकता है। कोविड महामारी की जंग दोनों देशों के आपसी तालमेल से कितनी और राहत मिल सकती है उस हालात में जब भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सामरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, आतंकवाद, हिंसा सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याओं पर हम विचार क्यों नहीं कर सकते। सत्ता और विपक्ष एक साथ मिलकर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभा सकता। सत्ता से बाहर आते ही विपक्ष की सारी जिम्मेदारियां क्यों खत्म हो जाती हैं। उसके लिए क्या देश और लोगों की समस्याएं कोई मायने नहीं रखती हैं। क्या सिर्फ सत्ता ही देश सेवा का अनूठा माध्यम है। बदले राजनीतिक दौर में सत्ता और विपक्ष दोनों में इसका नितांत अभाव दिखता है। सत्तापक्ष, विपक्ष को न भरोसे में लेना चाहती है और विपक्ष न सत्तापक्ष के भरोसे में आना चाहता है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश ने उसे जो दायित्व सौंपा है वह निभाए। अब उसी तरह की तस्वीर अमेरिकी यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल हुई तो सोशलमीडिया पर इसे शास्त्री की नकल बताया गया और उसकी आलोचना की जा रही है। सामान्य आदमी अगर अपनी तस्वीरें वायरल कर सकता है तो क्या प्रधानमंत्री को

यह अधिकार नहीं है। उसके पास अपनी कुछ इच्छाएं नहीं हैं। सत्ता और विपक्ष के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। लालबहादूर शास्त्री की तस्वीर को रीयल और मोदी की तस्वीर को रील बताया जा रहा है। देश के एक सम्मानित मीडिया हाउस की तरफ से भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, भारत रत्न अटल बिहारी, बाजपेयी और मनमोहन सिंह को विदेश यात्रा के दौरान विमान में कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस तरह के कार्य करते रहे हैं। एक दूसरी वायरल तस्वीर में एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के साथ एयर इंडिया का विमान दिख रहा है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता दिखाते हुए प्रधानमंत्री का विमान दिख रहा है जिस पर एयर इंडिया के बजाय भारत लिखा है। एक तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को विमान में सोते दिखाया गया है जबकि दूसरे में नरेंद्र मोदी की वह तस्वीर है जो हाल में वायरल हो रही है। यह साबित करने की कोशिश है कि मोदी काम करते दिख रहे हैं जबकि राजीव गांधी को सिर्फ विदेश यात्रा का शोक था। सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर यह भी वायरल है जिसमें 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कनाडा यात्रा के दौरान प्लेन से उतर रहे हैं तो उन्हें छाता दिखाया जा रहा है। जबकि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद छाता लेकर निकल रहे हैं हालांकि छाते वाली तस्वीर पर भी सोशल मीडिया पर आलोचना हुई है कि प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए विमान तल पर जो लोग खड़े थे वे छाता नहीं लिए थे, लेकिन मोदी छाता क्यों लिए थे। अब इन तथ्यहीन बहसों का क्या मतलब। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी की एक तस्वीर भी विदेश यात्रा की सोशलमीडिया में सुर्खियां बटोर रही है जिसमें विदेश यात्रा के दौरान काफी भीड़ उनके स्वागत में उमड़ी है। दावा किया गया है कि पंडित नेहरू के साथ इसी यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी का नाम %इंदिरा% पड़ा था। फिलहाल सोशलमीडिया पर इस तथ्य और दिशाहीन बहस से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि यह मौसमी कुतर्क है और राजनीति का दृढ़वाद है। सोशलमीडिया अच्छी भाषा और विचारों के बजाय सिर्फ कुतर्कों की गंगनी फैला रहा है। देश और समाज को बांटे का काम कर रहे हैं। हमें हर हालात में इस स्थिति से बचना होगा।

(लेखिका - निर्मल रानी)



होने वाला। जिस आंदोलन में दुग्धमुंहे बच्चे से लेकर सौ वर्ष से अधिक उम्र वाले अनेक बुजुर्ग डटकर सत्ता को चुनौती दे रहे हों, बहुमत के नशे में चूर सत्ता द्वारा उस आंदोलन को कमजोर या हल्का समझना निश्चित रूप से उसकी बड़ी भूल है। परन्तु इस प्रकार के भारत बंद से आम जनता को भी भारी परेशानी व जनसंकट का सामना करना पड़ता है। देश अब तक किसानों के इस भारत बंद के अलावा भी विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा जनसमस्याओं को लेकर या सत्ताविरोधी स्वर बुलंद करने के लिये सैकड़ों बार भारत बंद का सामना कर चुका है। और हर बार जनता को ट्रैफिक या जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई कई घंटों के जाम तो दिल्ली व आसपास के शहरों, महानगरों तथा देश के प्रमुख शहरों में बिना भारत बंद के ही आये दिन लगते रहते हैं। बारिश में भी जगह जगह लंबे समय तक जाम लगने की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। उस समय मीडिया आंशिक रूप से ऐसे जाम की खबरें तो जरूर देता है परन्तु उसके कारण व उनका जिम्मेदार कौन है इन बातों पर रौशनी नहीं डालता। जबकि किसानों द्वारा अपने व देश की जनता के हितों के मद्देनजर किये जा रहे ऐसे आंदोलनों में 'गोदी मीडिया' किसानों पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है तथा इस किसान आंदोलन को 'शाहीन बाग' आंदोलन के धरने से जोड़ने की कोशिश करता है। भारत बंद की सफलता और इसे मूक दर्शक बन रहकर देखने की देश व राज्य सरकारों की मजबूरी यह साबित करती है कि पूर्ण बहुमत की यह सरकार उसके अनुसार 'मुट्टी भर किसानों' के भारत बंद रूपी राष्ट्रव्यापी विरोध के आगे शक्तिहीन व असहाय रही। सरकार उस विपक्ष की रणनीतियों के आगे भी असफल दिखाई दी जिसपर वह किसानों को भड़काने व गुमराह करने का भी आरोप लगाती है साथ साथ उसी विपक्ष को मृत प्राय, कमजोर और कांग्रेस के लिये तो खासकर 'कांग्रेस मुक्त भारत' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करती रहती है। कांग्रेस के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन सी पी) आम

आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समेत दक्षिण भारत के कई राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता बंद के दौरान भारत बंद को सफल बनाने के लिये सड़कों पर उतरे नजर आए। भारत बंद की सफलता ने यह साबित कर दिया कि देश का किसान भी संगठित है और विपक्ष का भी किसानों को सर्वसम्मत व पूर्ण समर्थन हासिल है। सरकार को इस भारत बंद से सबक लेने की जरूरत है। अपने किसान विरोधी व जनविरोधी फ़ैसलों को संसद में बहुमत के आंकड़ों व रणनीतिपूर्ण चुनावी परिणामों से जोड़कर देखना सत्ता की भूल है। सरकार को महसूस करना चाहिये कि जहाँ सी ए ए व एन आर सी तथा तीन तलाक जैसे उसके कानून भारतीय समाज में उसकी सामाजिक विघटन की सोच को उजागर करते हैं उसी तरह तीन नए कृषि कानून व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (ह्रवअ) द्वारा निर्मित अनेक नियम कानून पूर्णतया: कृषक विरोधी हैं और यह सरकार की पूंजीवाद सूचक को भी प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि क्या वजह है कि सत्ता में आने के बाद उसके द्वारा एक के बाद एक लिये जा रहे नोटबंदी व जी एस टी जैसे तानाशाही पूर्ण फ़ैसले आखिर क्योंकर जनता को बेचैन कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान का द्विदोरा पीट व इसके कथित कीर्तिमान को लेकर अपनी पीठ थपथपा कर सरकार नदियों किनारे तैरती लाशों व ऑक्सिजन की कमी से तड़प कर मरने व चीखने चिल्लाने वाले दृश्य देशवासियों की नजरों से ओझल नहीं कर सकती। किसान संगठन बार बार कह रहे हैं कि जब तक किसान विरोधी तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बन जाता तब तक उनका आंदोलन व संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में अब सरकार को तय करना है कि वह किसानों से टकराने की अपनी झूठी-सच्ची रणनीति पर कायम रहना ही पसंद करती है या अपने अहंकार को समाप्त कर किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुँच कर देश को धरने, प्रदर्शनों व जाम तथा बंद आदि से निजात दिलाने की दिशा में यथाशीघ्र कोई सार्थक कदम उठती है।

आज का राशिफल

मेष	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई या पड़ोसी से तनाव मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं।
वृषभ	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। आर्थिक तथा व्यावसायिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
मिथुन	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
कर्क	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। विरोधी परास्त होंगे। धन लाभ की संभावना है।
सिंह	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।
कन्या	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
तुला	जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे।
वृश्चिक	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। वाद विवाद की स्थिति से बचें। आर्थिक योजना सफल होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
धनु	व्यावसायिक तथा आर्थिक योजना फलीभूत होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा।
मकर	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। किया गया परिश्रम सार्थक होंगे।
कुम्भ	रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
मीन	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। स्थानांतरण व परिवर्तन के योग हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ तैयार है बीएसई



नई दिल्ली। देश का प्रमुख शेयर बाजार बीएसई अपने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ तैयार है। बीएसई के मुख्य व्यवसाय अधिकारी समीर पाटिल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे देशभर में पीली धातु के लिए समान मूल्य ढांचा बनाने में मदद मिलेगी। पाटिल ने कहा कि एक्सचेंज जरूरी आंतरिक मंजूरी हासिल करेगा और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के पास अपने मंच पर नयी प्रतिभूति श्रेणी शुरू करने को आवेदन करेगा। इससे पहले सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को गोल्ड एक्सचेंज के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें पीली धातु में कारोबार ईजीआर के रूप में होगा और इससे एक पारदर्शी हाजिर मूल्य खोज तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी। अभी भारत में सिर्फ गोल्ड डेरिवेटिव्स और गोल्ड ईटीएफ की अनुमति है। वहीं अन्य देशों में सोने के भौतिक कारोबार के लिए हाजिर एक्सचेंज होते हैं। सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) कहा जाएगा और इसे प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ईजीआर में अन्य प्रतिभूतियों की तरह कारोबार, समाशोधन और निपटान की खूबियां होंगी।

एफपीआई ने सितंबर में भारतीय बाजारों में 26,517 करोड़ रुपये डाले

नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में भारतीय बाजारों में शुद्ध रूप से 26,517 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध लिवाब रहें हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने एक से 30 सितंबर के दौरान शेयरों में 13,154 करोड़ रुपये तथा ऋण या बांड बाजार में 13,363 करोड़ रुपये डाले। इस तरह उनका शुद्ध निवेश 26,517 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले अप्रैल में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 16,459 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इकटि तकनीकी शोध) श्रीकांत चौहान ने कहा, "ज्यादातर प्रमुख उभरते बाजारों में एफपीआई ने सितंबर माह में पूंजी डाली है। इस दौरान भारत में एफपीआई का प्रवाह सबसे ऊंचा रहा।" उन्होंने कहा कि इस दौरान दक्षिण कोरिया के बाजारों में एफपीआई का निवेश 88.4 करोड़ डॉलर, थाइलैंड में 33.8 करोड़ डॉलर और इंडोनेशिया में 30.5 करोड़ डॉलर रहा। मॉनिंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, "मौजूदा रुख से संकेत मिलता है कि एफपीआई अब लघु अवधि की चुनौतियों से आगे देखने लगे हैं और उनका ध्यान वृद्ध रुख पर है।" उन्होंने कहा कि एफपीआई धीरे-धीरे अपना सतर्कता का रुख छोड़ रहे हैं और भारतीय बाजारों के प्रति उनका भरोसा बढ़ रहा है।

दूरसंचार विभाग ने स्थानीय खरीद की सूची में राउटर, स्विच को जोड़ने का आदेश फिलहाल रोक

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सरकारी इकाइयों के लिए स्थानीय विनिर्माताओं से खरीदे जाने वाले दूरसंचार उपकरणों की सूची का विस्तार करने संबंधी अपने आदेश को फिलहाल रोक दिया है। विभाग ने 31 अगस्त को जारी अपने आदेश में एसडी-वान राउटर और स्विच समेत दो दर्जन अन्य दूरसंचार उपकरणों को स्थानीय निर्माताओं द्वारा खरीदे जाने वाली सूची में शामिल किया था। इनका उपयोग दूरस्थ शाखाओं और डेटा केंद्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। विभाग ने इसके अलावा इन उपकरणों के उपयोग के लिए आयात किये जाने वाले घटकों की अनुमति दे दी थी। अधिसूचना में कहा गया, "दूरसंचार विभाग द्वारा 31 अगस्त, 2021 को जारी किये गए आदेश को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। विभाग ने हालांकि इस फैसले को टालने का कारण नहीं बताया।"

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एसबीआई ने मनाया 'एनपीएस दिवस'

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) दिवस शुरू करने की घोषणा की। एनपीएस दरअसल देश में पेंशनभोगी समाज के गठन के लिए भारत सरकार के मिशन के तहत पीएफआरडीए के अभियान के अनुरूप है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने अपने लाखों ग्राहकों के बीच एनपीएस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी सभी शाखाओं में



इस पहल की शुरुआत की। हिस्से के रूप में योनि क्षेत्र के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों के खारा ने एनपीएस दिवस के एसबीआई पर सभी नागरिक लिए एनपीएस पंजीकरण

कार्यक्षमता भी शुरू की। इस अवसर पर बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, "हमें अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अनुरूप 'एनपीएस दिवस' मनाते हुए खुशी हो रही है। हमारा मानना है कि हमारे ग्राहकों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस में निवेश के महत्व को समझने का यह एक बेहतर अवसर है। हम एसबीआई में अपने ग्राहकों को एनपीएस के बारे में शिक्षित करना जारी रखेंगे जिससे उन्हें बहुत कम उम्र से ही अपने जीवन के सुनहरे दौर के लिए बचत की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी।"

ई-श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया: श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "पोर्टल पर अब तक 2.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं।" ई-श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। बयान के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि चौथे सप्ताह में 1.71 करोड़ से अधिक

असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो गया था, और इस (5वें)

अनुमान के मुताबिक करीब 38 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में

अवसर पर चंडीगढ़ के श्रम ब्यूरो भवन में क्षेत्र संबंधित प्रतिष्ठान



सप्ताह में कुल 2.51 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के

काम कर रहे हैं। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के

सर्वेक्षण (एफआईएस) के जमीनी कार्य को झंडी दिखाकर रवाना किया।

कृषकों, सीएससी में कृषि-आदान उत्पादों के विपणन के लिए हाथ मिलाया

नई दिल्ली। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज ने चार लाख ग्राम स्तर के उद्यमियों के जरिये किसानों की उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों (इनपुट) तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषक भारतीय कोऑपरेटिव (कृषको) से हाथ मिलाया है। एक बयान में कहा गया है कि साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिये कृषकों उत्पादों की बिक्री और विपणन किया जाएगा। इनमें उर्वरक, मसलन आयातित यूरिया, डीएपी, एनपीके/एनपीएस, जैव-उर्वरक, सिटी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट, प्रमाणीकृत बीज और हार्डब्रिड बीज जैसे उत्पाद शामिल हैं। कृषकों द्वारा उर्वरकों, कृषि

आदानों तथा बीजों का विनिर्माण, आयात और विपणन किया जाता है। इससे पहले इसी साल सीएससी ने बीज, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि मशीनरी को किराये पर देने या लेने तथा अपने वीएलई तथा कृषक उत्पादक संगठनों के जरिये कृषि उपज के कारोबार के लिए कृषि सेवा मंच का गठन किया था। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि कृषकों के साथ हमारी भागीदारी सरकार के किसानों और कृषक समुदाय को सेवा के एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

अमेज़न, फ्लिपकार्ट की त्योहारी बिक्री की जोरदार शुरुआत, टियर 2-3 शहरों में तेजी

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़न इंडिया ने कहा कि इस साल उनकी त्योहारी बिक्री की मजबूत शुरुआत हुई है और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों की मांग में खासतौर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

वाॅलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसके 'फ्लिपकार्ट प्लस' कार्यक्रम (लॉयल्टी प्रोग्राम) के लिए पिछले साल की तुलना में इस साल 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि ग्राहकों की लगभग 45 प्रतिशत मांग टियर-3 शहरों और उससे बाद के शहरों से है।

एक अलग बयान में अमेज़न इंडिया के उपाध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि 'अमेज़न डॉट इन' पर सालाना आधार पर सर्वाधिक एकल दिवस बिक्री हासिल करने वाले विक्रेताओं की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि हमारे महीने भर चलने वाले उत्सव 'अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2021' की मजबूत शुरुआत हुई है, जिसमें लाखों ग्राहक अमेज़न पर पंजीकृत छोटे विक्रेताओं से खरीदारी कर रहे हैं। इन दुकानदारों में स्थानीय दुकानें, स्टार्ट-अप और ब्रांड, कारीगर और बुनकर शामिल हैं। तिवारी ने कहा, "दो अक्टूबर को प्राइम ग्राहकों के लिए शीघ्र पहुंच के दौरान पिछले साल की तुलना में इस साल आयोजन में शामिल होने वाले स्थानीय दुकानदारों की संख्या दोगुनी से अधिक हो

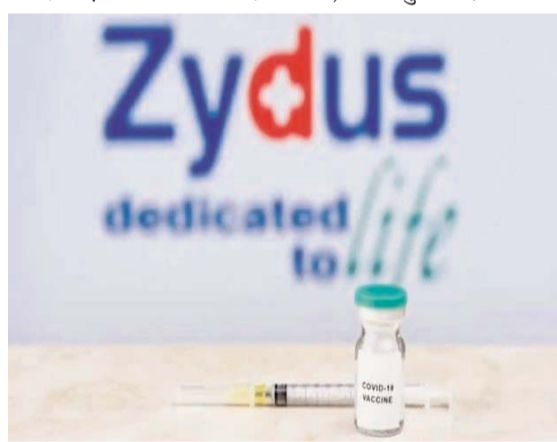
गई।" उन्होंने कहा कि प्राइम सब्सक्रिप्शन पूरे भारत में ग्राहकों की पसंद बना हुआ है, तीन में से दो नए प्राइम ग्राहक टियर-2 और टियर-3 शहरों से आते हैं। फ्लिपकार्ट ने अपने बयान में कहा कि उसके टीबीबीडी के आठवें संस्करण की शुरुआत सकारात्मक रही। बयान में कहा गया, "फ्लिपकार्ट के जरिए ग्राहकों के लिए शुरुआती पहुंच में पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि ग्राहकों की लगभग 45 प्रतिशत मांग टियर-3 शहरों से आ रही है।"

जायडस कैडिला ने 1900 रुपये में कोविड वैक्सीन की तीन खुराकों की पेशकश, सरकार कर रही मोलभाव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और जायडस कैडिला के बीच कोविड-19 वैक्सीन जायकोव-डी की कीमत को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे 12 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। दवा कंपनी ने जायकोव-डी की तीन खुराकों 19,00 रुपये में देने की पेशकश की है। हालांकि, सरकार कीमतों को कम करने के लिए मोलतोल कर रही है और इस पर अंतिम फैसला इसी सप्ताह किए जाने की संभावना है। सरकार ने कहा था कि जायडस कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया की पहली डीएनए-आधारित सुई-रहित कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल जल्द ही शुरू किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया, "कंपनी ने अपनी तीन खुराकों के लिए करों सहित 1,900 रुपये की कीमत का प्रस्ताव किया है।" उन्होंने बताया, "बातचीत जारी है। कंपनी को टीके की लागत के बारे में सभी पहलुओं पर फिर से विचार करने

के लिए कहा गया है। वैक्सीन की कीमत पर अंतिम फैसला इसी सप्ताह किए जाने की संभावना है।

कीमत 30,000 रुपये है। एक जेट इंजेक्टर का उपयोग लगभग 20,000 खुराक देने के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन की दूसरी और तीसरी खुराक, पहली खुराक के 28 और 56 दिन बाद दी जानी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र और कंपनी के बीच अब तक करीब तीन दौर की बैठक हो चुकी है और आखिरी गुरुवार को हुई।



नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे

नई दिल्ली। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूटीपी) ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव समारोह के तहत विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि स्थापना के बाद से अपने पांचवें वर्ष में वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स (डब्ल्यूटीआई) 2021 'सशक्त और समर्थ भारत' की दिशा में वह उन महिला उद्यमियों के योगदान का जश्न मनाएगा, जिन्होंने आत्मनिर्भर



के जरिये चुनौतियों पर जीत हासिल की है। इस साल

डब्ल्यूटीआई पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र, सिस्को सोएसआर, फिक्की रहे हैं। एक आधिकारिक विज्ञापि में कहा गया कि आवेदन डब्ल्यूटीपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आवेदन 31 दिसंबर, 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। महिला उद्यमिता अपना नामांकन खुद कर सकती है या उन्हें दूसरों द्वारा नामित भी किया जा सकता है। नामांकन सात श्रेणियों - सार्वजनिक तथा सामुदायिक सेवा, विनिर्माण क्षेत्र, गैर-विनिर्माण क्षेत्र, आर्थिक विकास को सक्षम करने वाले वित्तीय उत्पाद, जलवायु संबंधी कार्रवाई, कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प और डिजिटल नवाचार - में कराये जा सकते हैं।

टाई हैदराबाद चैप्टर की सामाजिक उद्यम के लिए 20-30 करोड़ डॉलर के कोष की योजना

नई दिल्ली। उद्यमियों के संगठन टाई हैदराबाद ने कहा कि वह वैश्विक सामाजिक योगदान के लिए आगामी टाई स्थिरता शिखर सम्मेलन में 20-30 करोड़ डॉलर के सामाजिक प्रभाव कोष की शुरुआत करेगा। इस कोष की मदद से वैश्विक सामाजिक उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मदद दी जाएगी। टाई ग्लोबल चैप्टर और टाई हैदराबाद के अध्यक्ष मनोहर रेड्डी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शुरू हो रहे तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान यह कोष बढ़कर 40 करोड़ डॉलर तक हो सकता है। इसके अलावा टाई हैदराबाद शिखर सम्मेलन के जरिये सामाजिक उद्यमियों को टाई ग्लोबल के 10 करोड़ डॉलर के कोष में भाग लेने का मौका भी मिलेगा।

उन्होंने कहा, "हमारे पास जमीन पर सामाजिक विभिन्न सरकारों से अपेक्षित है, जिसमें से प्रभाव पैदा करने वाले स्टार्ट-अप और ज्यादातर अनुदान के रूप में होंगी। अनुदान की

रशि व्यवसाय की प्रकृति और उसके जमीन पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगी।"



नियुक्ति: यूको बैंक के अगले प्रबंध निदेशक हो सकते हैं सोम शंकर प्रसाद, पीएम की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति लगाएगी अंतिम मुहर

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उप-प्रबंध निदेशक सोम शंकर प्रसाद को कोलकाता स्थित यूको बैंक का अगला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है। पीएनबी के प्रबंध निदेशक का पद

जनवरी में एस एस मल्लिकार्जुन राव की सेवानिवृत्ति के बाद से रिक्त है। सूत्रों ने बताया कि इस साल इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के समय प्रसाद का नाम आरक्षित सूची में था। सतर्कता सहित विभिन्न मंजूरीयों के बाद उन्हें यूको बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। बोर्ड ने निदेशक पद के लिए लिया था इंटरव्यू



सूत्रों ने कहा कि इस बारे में अंतिम बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है।

निर्णय प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस साल मई में इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक पद के लिए साक्षात्कार लिए थे। साक्षात्कार के बाद शांति लाल जैन को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। उस समय प्रसाद आरक्षित सूची में थे। पहली तिमाही में यूको बैंक का

शुद्ध लाभ चार गुना बढ़ा भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने यूको बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर किया था। विभिन्न मानदंडों में सुधार के बाद बैंक को पीसीए से बाहर किया गया था। चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में यूको बैंक का शुद्ध लाभ चार गुना होकर 101.81 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।

सार समाचार

कैथोलिक चर्च में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों की संख्या 3,000 के हो सकती है पार!

पेरिस। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च में बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे स्वतंत्र आयोग का मानना है कि पिछले 70 साल में चर्च में काम करने वाले पादरियों में से दो तिहाई यानी लगभग 3,000 लोग यौन उत्पीड़न में शामिल रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष ज्या-मार्क सीवे ने अखबार जर्नल दू दिमांश में रविवार को प्रकाशित साक्षात्कार में यह अनुमान व्यक्त किया है। आयोग लगभग ढाई साल से इस मामले में पड़ताल कर रहा है। इसके अंतिम पूर्ण नतीजे मंगलवार को जारी किये जा सकते हैं। यौवने में यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की संख्या नहीं बताई लेकिन कहा कि रिपोर्ट में नया आकलन शामिल है। बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि 1950 के दशक से काम करने वाले चर्च के 11,500 पादरियों और अन्य लोगों में से उनकी संख्या 3,000 है।"

जॉर्ज फ्लॉयड की याद में बनाई गई प्रतिमा को किया गया नष्ट

न्यूयॉर्क (अमेरिका)। न्यूयॉर्क सिटी के यूनिवर्सिटी पार्क में अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के सम्मान में बनाई गई प्रतिमा को रविवार को विरूपित किया गया। पुलिस ने बताया कि एक वीडियो में दिखा रहा है कि स्कैटबोर्ड पर आए एक अज्ञात व्यक्ति ने सुबह करीब 10 बजे प्रतिमा पर पेट फेंका और इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने वीडियो जारी नहीं किया है। दिवंगत सांसद जॉन लुइस और पिछले साल पुलिस की कार्रवाई में मारी गई केंद्री के लुइसविले की ब्रेओना टेलर की पास ही स्थापित प्रतिमाओं को स्पष्ट रूप से छुआ नहीं गया। फ्लॉयड की याद में बनाई गई प्रतिमा को विरूपित करने की घटना पहली बार नहीं हुई है। इस प्रतिमा के अनावरण के पांच दिन बाद ही इस पर काला पेट फेंका गया था और उस पर श्वेतों को सर्वोच्च मानने वाले एक समूह का कथित चिह्न भी लगाया गया था। मिनिआपोलिस में पुलिस की कार्रवाई में फ्लॉयड की मौत होने के कारण देशभर में नरसी भेदभाव को लेकर आंदोलन हुआ था।

भारतीय मूल के आठ अमेरिकियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया

वाशिंगटन। भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकियों को वर्जीनिया राज्य के 'पेटर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन' (जीओपीआईओ) ने सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए रविवार को सम्मानित किया। डॉ. वीके राजू को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, डॉ. विक्रम राया को उद्यमिता के क्षेत्र में, राम बी गुप्ता को शिक्षा, कोरक रे को नवाचार और अनुसंधान में, इंदुजीत एस सलूजा को पत्रकारिता के क्षेत्र में, नीलिमा मेहरा को मीडिया में, विनीता तिवारी को कला और संस्कृति के क्षेत्र में तथा जेनेथा रेड्डी को अधिकांश कार्यों और पारोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

अरब क्षेत्र में हिंसा पर अंकुश लगाने के लिये सेना और सुरक्षा एजेंसियों की भर्ती: इजराइल

यरूशलेम। इजराइल सरकार ने रविवार को कहा कि देश के अरब क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सेना एवं शीन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी की भर्ती की जा रही है। देश में अरब अल्पसंख्यक हाल के वर्षों में हिंसक अपराध से प्रभावित हुये हैं, और हत्या दर देश की आबादी में उनके प्रतिशत से कई अधिक है। विशेष मंत्री समिति बैठक को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नाफाली बेनेट ने कहा कि हिंसा अब चरम पर पहुंच गयी है और उनकी सरकार इसे गंभीरता पूर्वक ले रही है।

पड़ोरा पेपर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी लोगों समेत 700 से अधिक लोगों के नाम

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी लोगों और कुछ मंत्रियों समेत 700 से अधिक लोगों के नाम पड़ोरा पेपर मामले में सामने आए हैं। पड़ोरा पेपर में विश्व भर में उच्च पदों पर आसीन लोगों के गुप्त वित्तीय लेन-देन का खुलासा किया गया है। टेलीविजन समाचार चैनल जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजेन) ने रविवार को 'पड़ोरा पेपर' का खुलासा किया, जिसके अनुसार वित्त मंत्री शौकत तारिन, जल संसाधन मंत्री मुनिस झहरी, सांसद फैसल वावडा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुदरोस बहिनवार के परिवार समेत अन्य लोगों के विदेशी कंपनियों से लेन-देन के संबंध थे। इस मामले में कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, व्यवसायियों और मीडिया कंपनी के मालिकों के नाम भी सामने आए हैं।

मनीला मेयर आधिकारिक तौर पर 2022 की राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल

मनीला। मनीला के मेयर फ्रांसिस्को डोमागोसो ने सोमवार को फिलीपींस में मई 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी का प्रमाण पत्र दाखिल किया। समाचार एजेंसी रिपोट के अनुसार, 46 वर्षीय डोमागोसो अपने सेलिब्रिटी उपायन इस्क्री मोरनो के नाम से लोकप्रिय हैं और उनके चल रहे साथी विली ऑंग, जो फेसबुक पर 1.6 करोड़ से अधिक अनुयायियों के साथ एक डॉक्टर हैं ने चुनाव आयोग में उम्मीदवारी का प्रमाण पत्र दाखिल किया। फिलीपीन की राजधानी के मेयर राजनीतिक दल अवस्थान डेमाक्रेटिको के अधीन चलेंगे, जिसके वे अध्यक्ष हैं। पत्न्य परिषदा द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार, फिलिपिनो उतरदाताओं में से 13 प्रतिशत ने संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में डोमागोसो के लिए समर्थन व्यक्त किया। 1 अक्टूबर को, फिलिपिनो बॉक्सिंग आइकन और सीनेटर मैनी पैकिकिओ अपना आधिकारिक प्रमाण पत्र दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार बन गए, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बॉक्सिंग से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 9 मई, 2022 के चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 24 सदस्यीय सीनेट के आधे, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों और अन्य स्थानीय अधिकारियों का चुनाव करेगा।

ताइवान के खिलाफ ड्रैगन का हवाई अटैक प्लान, भड़के अमेरिका ने दी वॉर्निंग

कोलंबो। (एजेंसी)।

ताइवान और चीन के बीच दशकों से तनाव है। चीन जबरन तरीके से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, ये हकीकत भी पूरी दुनिया को पता है। जिस तरीके से एक छोटे से मुल्क को चीन डराने धमकाने में लगा है वो हुरान करने वाला है। पिछले एक साल से ड्रैगन की सेना ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही है। चां हो जमीन पर हो समुंद्र में हो या आसमान में लगातार तीनों फ्रंट से ड्रैगन की उकसावे वाली हरकतें सामने आई है। लेकिन अब ताइवान के आसमान में ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे मुल्क में खलबली मच गई है। एक साथ 39 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। वो भी बम, गोला-बारूद और मिसाइलों के साथ।

ताइपे के एयरजोन में दंगी प्लेन

पूरी प्लानिंग के साथ ड्रैगन की हवाई सेना ने ताइवान के हवाई स्पेस में घुसपैठ की वो भी खुलेआम। ताइवान की सेंट्रल



न्यू एजेंसी की मांनें तो चीनी फाइटर पॉयलट्स ने पीएलए ईस्टर्न थियेटक कमांड से मिले ऑर्डर के बाद घुसपैठ में अपने सबसे विस्फोटक घातकआसमानी लड़ाकों

के साथ घुसपैठ की। जिन चीनी विमानों ने ताइवान में एंटी ली थी उनमें से ज्यादातर की पहचान जे-17 और सू-30 फाइटर जेट के रूप में की गई।

अमेरिका की चेतावनी

अब इस मामले पर अमेरिका भी भड़क गया है और उसने चीन को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने इस मामले पर चीन से उसकी उकसाने वाली सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने बयान में कहा कि हम बीजिंग से अपील करते हैं कि वह ताइवान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई न करे।

चीन-ताइवान विवाद

गुह युद्ध के पश्चात 1949 के दौर में चीन और ताइवान दोनों अलग हो गए थे। एक तरफ जहां कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर शासन किया वहीं उसके विपरीत नेशनलिस्ट समर्थकों ने ताइवान की बागडोर संभाली। ताइवान चीन के पूर्वी तट से 160 किलोमीटर दूर है और उसकी आबादी 2.40 करोड़ है। चीन पिछले एक साल से अधिक समय से ताइवान के दक्षिण में लगातार सैन्य विमान भेज रहा है।

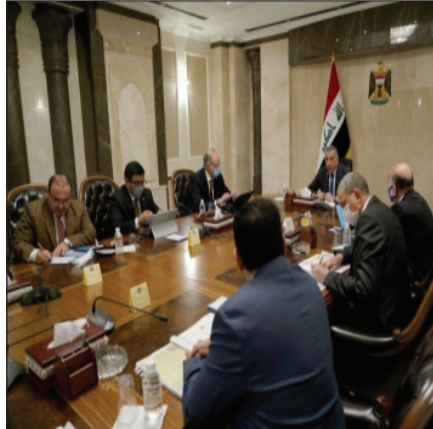
आत्मघाती कार बम विस्फोट हुआ विफल, इराकी प्रधानमंत्री ने सुरक्षा सदस्य को किया सम्मानित

वगदद (एजेंसी)।

सेना ने बताया कि इराकी प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने पश्चिमी प्रांत अनवर में एक आत्मघाती कार बम विस्फोट को विफल करने वाले एक सुरक्षा सदस्य को सम्मानित किया है। समाचार एजेंसी ने रविवार को जारी इराकी ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड (खडड) के मीडिया कार्यालय द्वारा दिए गए एक बयान के हवाले से कहा कि अल-कदीमी ने हामिद शुएब अब्दुल्ला को एक उच्च सैन्य रैंक में पदोन्नत करने और कार बम का सामना करने के लिए उनके साहस के लिए वित्तीय इनाम देने का आदेश दिया है। इससे पहले दिन में, जेओसी ने एक बयान में कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने बगदाद से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम

में रमादी में अपनी कार बम विस्फोट किया था, जब सुरक्षा बलों ने उस पर मानवों को हताहत किए बिना गोलियां चलाई थी।

हालांकि, एक प्रांतीय सुरक्षा सूत्र ने गुमान रूप से सिन्हुआ को बताया कि भीषण विस्फोट में आत्मघाती हमलावर की मौत हो गई और पांच नागरिक घटनास्थल पर ही घायल हो गए थे। पिछले कुछ महीनों में, इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने इराकी सुरक्षा बलों पर उन प्रांतों में हमले तेज कर दिए हैं जिन पर समूह पहले से नियंत्रण कर रहा था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए। 2017 में आईएस को हराने के बाद से इराक में सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि, आईएस के अवशेष सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ लगातार हमले करते रहे हैं।



बदस्थां में 600 विस्थापित अफगान नागरिक अपने घर लौटे

काबुल (एजेंसी)।



तालिबान के अधिग्रहण से पहले के महीनों में नागरिक लड़ाई से विस्थापित हुए करीब 600 अफगान नागरिक अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र से उत्तरी बदस्थां प्रांत में अपने घरों को लौट गए हैं।

प्रांतीय गवर्नर मौलवी अमानुद्दीन मंसूर ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंसूर ने कहा कि 15 अगस्त को तालिबान के राजधानी काबुल के अधिग्रहण से पहले संघर्ष के दौरान वापसी करने वाले लोग विस्थापित हो गए थे। उन्होंने कहा, वे खुले मैदान में विकट स्थिति में रह रहे

थे। प्रांतीय अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वे वापस लौटे हैं। गवर्नर के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्र में सभी विस्थापित लोगों को जल्द से जल्द अपने गांवों में लौटने में मदद करने के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि सर्दी शुरू होने वाली है। इस प्रांत पर 10 अगस्त को तालिबान का कब्जा हो गया था। पिछले महीने के अंत में, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएल) ने कहा कि अफगानिस्तान में इस साल 6,35,000 से अधिक लोगों को मजबूरी में हिंसा के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है, जिसमें 12,000 से अधिक लोग काबुल में विस्थापित हुए हैं।

विदेश सचिव हर्षवर्धन ने श्रीलंकाई पीएम महिंदा राजपक्षे के साथ सकारात्मक वार्ता की पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा, उसका बायकाँट करना होगा- बेल्जियम के सांसद का बड़ा बयान

कोलंबो। (एजेंसी)।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की और उनसे बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर 'सकारात्मक वार्ता' की। श्रृंगला चार दिन की यात्रा



पहले ही मैंने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बहुत सकारात्मक वार्ता की। वह भारत के प्रगाढ़ मित्र हैं और भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहन करने के लिए समर्थन का सतत स्रोत हैं। विदेश सचिव ने कहा कि वह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से अपनी मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं। महिंदा राजपक्षे ने ट्वीट कर श्रृंगला से मुलाकात पर प्रसन्नता जताई। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा, "श्रीलंका की सरकार दोनों देशों को परस्पर लाभ पहुंचाने के लिए हमारे पहले से मजबूत संबंधों को

और सुदृढ़ करने के लिहाज से भारत सरकार के साथ काम करने को लेकर अशान्चित है।" श्रृंगला ने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर कोलंबो स्थित टैम्पल ट्रीज में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, "महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रोफेसर जी एल पेड़ूरिस, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के उच्चायुक्त और अन्य गणमान्यों ने टैम्पल ट्रीज में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।" श्रृंगला ने रविवार को श्रीलंका के तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में जाफना के पलानी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया था जहां भारत की सहायता से किये जा रहे विकास कार्यों पर अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी।

कोलंबो। (एजेंसी)।

ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पनाह देने वाला पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है इस बात से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है और अब तो नोबत ऐसी है कि तालिबान का सपोर्ट करने के चक्र में पाकस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकुमत का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का अब कई देश खुलकर विरोध कर रहे हैं।हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लंदन दौर पर आए थे जहां उनका जमकर विरोध हुआ। वहीं बेल्जियम देश भी पाकिस्तान का खुलेआम विरोध करता नजर आ रहा है। उत्तरी यूरोप के देश बेल्जियम ने पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश करार दिया है। एक खबर के मुताबिक,बेल्जियम के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बेल्जियम के सांसद फिलिप डेविन्टर ने खुलेआम पाकिस्तान को आतंकी देश बताया और पाक के हस्तगत पर चिंता भी जाहिर की।



पाकिस्तान का करें बायकाँट!

बेल्जियम के सांसद फिलिप डेविन्टर ने आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के साथ रिश्ता नहीं रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि, तालिबान की तरह पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक खतरा है। फिलिप डेविन्टर ने यूरोपीयन यूनियन की राजनीतिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे कहा कि, पाकिस्तान पूरे क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर भी देता आएगा। उन्होंने दुनियाभर के देशों से पाकिस्तान को बायकाँट करने के लिए कहा है।

मिसाइल परीक्षणों के बावजूद दोनों कोरियाई देशों ने बहाल की हॉटलाइन, क्या सुधरेंगे हालात

सियोला। (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने कई सप्ताह से ठप पड़ी संचार 'हॉटलाइन' को सोमवार को फिर बहाल कर दिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई मिसाइल परीक्षण करने के साथ ही उत्तर कोरिया के साथ 'हॉटलाइन' बहाल करने की इच्छा जाहिर की थी। सियोल के एकीकरण मंत्रालय ने बताया कि दोनों कोरियाई देशों के सम्पर्क अधिकारियों ने सोमवार सुबह सीमा पार संचार चैनल पर संदेशों का आदान-प्रदान किया। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, सियोल के अधिकारी ने एक चैनल पर अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कहा, "लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम खुश हैं कि

हमारे संचार चैनल इस तरह बहाल हुए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच संबंध नए स्तर पर विकसित होंगे।" वीडियो में उत्तर कोरिया की ओर से कोई वक्तव्य नहीं था। सियोल के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक अलग सैन्य चैनल पर, दोनों कोरियाई देशों ने अपनी विवादित पश्चिमी समुद्री रोकने के लिए जाणकारी का आदान-प्रदान किया, जहां पिछले वर्षों में कई अंतर-कोरियाई हिंसक नौसैनिक युद्ध हुए हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए जाणकारियों का आदान-प्रदान किया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोनों कोरियाई देश अपनी तनावपूर्ण सीमा पर अन्य संचार माध्यमों को भी सोमवार को बहाल कर देंगे, क्योंकि दोनों ने पूर्व में ऐसे इरादे जाहिर किए हैं। फोन और फेक्स माध्यम भी एक वर्ष

से अधिक समय से निष्क्रिय हैं, जिनका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी कोरिया बेटवर्क करने, सीमा पार करने की व्यवस्था करने और आकस्मिक झड़पों से बचने के लिए करते हैं। गर्मियों में संचार को लागू दो सप्ताह के लिए सक्षिप्त रूप से बहाल किया गया था, लेकिन दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ वार्षिक सैन्य अभ्यास शुरू करने के बाद उत्तर कोरिया ने संदेशों का आदान-प्रदान करने से इनकार कर दिया। इस वार्षिक सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया युद्ध का पूर्वान्धास करार देता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शांति स्थापित करने के लिए अक्टूबर के शुरू में दक्षिण कोरिया के साथ 'हॉटलाइन' बहाल करने की इच्छा पिछले सप्ताह व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने वार्ता के अमेरिकी प्रस्ताव को यह कहकर फिर से ठुकरा

दिया था कि यह उत्तर कोरिया के खिलाफ शत्रुता को छुपाने का अमेरिका का "कूटिल तरीका" है। उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और अन्य घटनाक्रम के लिए अपने "दोहरे व्यवहार के दृष्टिकोण" और "शत्रुतापूर्ण नजरिए" को छोड़ने की मांग की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील और अन्य रियायतें देने के लिए राजी कर पाए। उत्तर कोरिया की आधिकारिक 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' ने 'हॉटलाइन' बहाल होने से पहले कहा था, "दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को उत्तर-दक्षिण संबंधों को सही रास्ते पर लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए और संघर्ष लाहनों की बहाली को ध्यान



में रखते हुए, भविष्य में उच्चल संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना चाहिए।

सार समाचार

कोलकाता की एक इमारत में लगी भीषण आग, घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 14 गाड़ियां

कोलकाता (कोलकाता के भीड़भाड़ वाले कोल्टोला इलाके में सोमवार को सुबह एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग तीसरी मंजिल पर पूर्वाह्न करीब 11 बजे लगी और इसमें किसी के झुलसने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए दमकल के 14 वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत के उन कमरों में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे थे और दो परिवार वहां रहते हैं। हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने की एक टीम और आपदा प्रबंधन विभाग भी बचाव अभियान में शामिल है। अधिकारी ने बताया, 'हमारी कोशिशें जारी हैं। इमारत के अंदर ज्वलनशील सामग्री भी रखी है।' अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।

तमिलनाडु में हत्यारे बाघ की खोज में जुटी वन विभाग की टीम

चेन्नई। एमडीटी 23 कोडनेम एमडीटी 23 के हत्यारे बाघ का पता लगाने और उसका शिकार करने के लिए खोज में जुटी वन तलाशी टीम ने अब तमिलनाडु के मसीनागुडी और सिंगारा इलाकों में अपनी खोज बढ़ा दी है। हत्यारे बाघ को ट्रैक करने के लिए दो कुम्भी हाथियों को सेवा में लगाया गया है। वन क्षेत्रों में फेंकी टास्क फोर्स में हाथी, उदयन और श्रीनिवास फिर से शामिल हो गए हैं। मुख्य कन्यजीव वाईन, तमिलनाडु, शेखर कुमार नीरज ने शनिवार को गुडलुरु में वन क्षेत्र की सीमा से लगे गांव के इलाकों में चार पुरुषों और 12 मवेशियों की मौत के बाद स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद बाघ को मारने का आदेश दिया था। वन अधिकारियों के अनुसार, बाघ स्वस्थ नहीं है और इसलिए वह जंगल में अपने शिकार का शिकार करने में सक्षम नहीं है और उसने अपने शिकार को आसानी से खोजने के लिए मानव बस्तियों में जाने की आदत बना ली है। बाघ अब तक चार आदिमियों को मार चुका है। तलाशी टीम में शामिल वन अधिकारियों ने आदिम जनसंख्या से बात करते हुए कहा, बाघ भूखा है और हमारी जानकारी के अनुसार उसने पिछले बहतर घंटों से खाना नहीं खाया है और निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगा। तमिलनाडु वन विभाग के लगभग 60 वन कर्मी और केरल वन विभाग के टाइगर ट्रैकर पिछले कुछ दिनों से बाघ का शिकार करने के लिए अभियान में हैं, लेकिन बाघ नहीं मिल रहा है।

उत्तर कर्नाटक में बार-बार भूकंप की सूचना के लिए अध्ययन पैनल स्थापित करेगी सरकार

विजयपुरा (कर्नाटक)। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के दो अलग-अलग हिस्सों में पिछले 48 घंटों में 2.7 तीव्रता से कम या रिक्टर पैमाने पर भूकंप की सूचना मिली है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग आशंकित और घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक महीने में पांच बार भूकंप का अनुभव किया है। लोगों ने पृथ्वी से निकलने वाली तेज आवाजों की भी सूचना दी और जब भी वे झूठे सुनते हैं, वे अपने घरों के बाहर दौड़ पड़ते हैं। जानकारों का कहना है कि दक्षिण भारतीय प्लेटों के उत्तर भारत की ओर बढ़ने से लगातार झटके आ रहे हैं। इस बीच, राज्य सरकार गहन अध्ययन के लिए एक उपसमिति का गठन कर सकती है। पिछले 7 दिनों के दौरान, विजयपुरा में 3.1 और दो की तीव्रता 2.0 और 3.0 के बीच भूकंप आए हैं। सबसे बड़ा भूकंप बीजापुर शहर के दक्षिण में 1 अक्टूबर को और सबसे हाल ही में 2 अक्टूबर को 2.3 तीव्रता के साथ दर्ज किया गया था।

यदि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड का उल्लेख नहीं है तो 50 हजार रुपये की सहायता राशि से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 से मरने वालों के परिवार के सदस्यों को 50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करें और सहायता राशि के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करें। पीठ ने साथ ही सरकार को इस स्कैम का व्यापक प्रचार करने के लिए भी कहा। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को इस आधार पर 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करना चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोविड-19 नहीं अंकित है और जिला अधिकारियों को मृत्यु के कारण को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। पीठ ने न्यायमूर्ति ए.एस. बोपाजा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रतिक्रिया के बाद होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिकायत निवारण समिति मृतक मरीज के मेडिकल रिकॉर्डों की जांच कर सकती है और मुआवजे पर 30 दिनों के भीतर फैसला ले सकती है। ऐसे मामलों में जहां मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं और परिवार के सदस्य उन पर उल्लिखित मृत्यु के कारण से परेशान हैं, तो वे समिति से संपर्क कर सकते हैं और प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया भूपेश बघेल और रंधावा का विमान लखनऊ में नहीं उतरने देने का अनुरोध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ आ रहे छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा को स्थानीय चौधरी रणज सिंह हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अनीश कुमार अवस्थी ने प्राधिकरण को रविवार देर रात लिखे पत्र में कहा है कि लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को हुए संघर्ष की घटना के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

किसान संगठन पर रूढ़ का फूटा गुस्सा, कहा- तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई तो किसके खिलाफ विरोध?

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जब तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है, तो किसान संगठन किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविशंकर की पीठ ने कहा कि कानूनों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के बाद ऐसे विरोध प्रदर्शन करने का सवाल ही कहा उठता है। अर्दानी जनरल के के वेणुगोपाल ने रविवार की लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र किया, जिसमें आठ लोग मारे गए थे। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई घटना होने पर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई मामला जब सर्वोच्च संवैधानिक अदालत के समक्ष होता है, तो उसी मुद्दे को लेकर कोई भी सड़क पर नहीं उतर सकता। शीर्ष अदालत तीन नए कृषि कानूनों के



विरोध में एक किसान संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यहां जंतर मंतर पर 'सत्याग्रह' करने की अनुमति देने का प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत कृषकों के

संगठन 'किसान महापंचायत' और उसके अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण एवं गैर-हिंसक 'सत्याग्रह' के आयोजन के लिए कम से

कम 200 किसानों के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है। पीठ ने तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर किसान संगठन की याचिका भी अपने यहां स्थानांतरित कर लिया। कई किसान संगठन तीन कानूनों - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, 2020 के पारित होने का विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों का विरोध पिछले साल नवंबर में पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैल गया।

लखीमपुर हिंसा मामले की कराई जाएगी न्यायिक जांच, मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे 45 लाख

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत की खबर है इनमें 4 किसान भी हैं। इन सबके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सरकार जिन 4 किसानों की हिंसा में मौत हुई है उनके परिवार को 45 लाख देगी। साथ ही साथ एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर एफ आई आर दर्ज की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे।

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर दौरान नहीं करने दिया गया है। हालांकि किसान संघों के कुछ सदस्यों को यहां आने की अनुमति दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और इसमें शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही मौके पर शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, कार्मिक एवं कृषि, एडीजी कानून व्यवस्था, आयुक्त लखनऊ तथा आईजी लखनऊ मौजूद हैं तथा स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं।



सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि घटना में लिप्त जो भी जिम्मेदार होगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों से अपील है कि वे अपने घरों पर ही रहे और किसी के

बहकावे में ना आए। साथ ही साथ मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। किसी प्रकार के निरक्षर पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच तथा कार्यवाही का इंतजार करें।

पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, यूपी सरकार को लिखा पत्र

चंडीगढ़। (एजेंसी)।

पंजाब नागरिक उड्डयन विभाग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने का आग्रह किया ताकि वह लखीमपुर खीरी जा सकें, जहां एक दिन पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर यात्रा से पहले रविवार को हुई इस घटना में मृतकों में किसान और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं।

पंजाब के नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनीश कुमार अवस्थी को पत्र लिखकर कहा, "जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत और उससे उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री इस दुख की घड़ी में संबंधित



किसानों के परिवारों से मिलना चाहते हैं।' विभाग ने कहा, "आग्रह किया जाता है कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने और फिर वहां से रवाना होने की मंजूरी दी जाए। यह भी अनुरोध है कि पर्याप्त व्यवस्था

की जाए ताकि मुख्यमंत्री संबंधित किसानों के परिवारों से मिल सकें।" इससे पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा था कि वह हालात का जायजा लेने लखीमपुर खीरी जाएंगे।

अमीर-गरीब की खाई को दूर कर रही है मोदी सरकार: अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र की तीन सड़कों का किया लोकार्पण



हमीरपुर। (एजेंसी)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड की गई तीन सड़कों चमारडा-

रचित्यां, मानपुल-भरमोटी और पनियाली-समजल सड़क का लोकार्पण किया।

इन सड़कों के लोकार्पण के बाद भरमोटी में जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमीर-गरीब की खाई को दूर करने तथा आम लोगों का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए सात वर्षों के

दौरान सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष बल दिया है। देश के लगभग 43 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे इन लोगों के खातों में डाल रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए भरपूर बजट उपलब्ध करा रही है। मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से भी पंचायतों को सीधा पैसा दिया जा रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं को इस बजट का सदुपयोग करना चाहिए तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से अधिक से अधिक शैल्फ डालने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के बजट में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। पंचायत जनप्रतिनिधि मनरेगा में कार्य करने वाले लोगों का श्रमिक

कल्याण बोर्ड में पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि वे बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकें।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से इस माह चलाए जा रहे क्वीन इंडिया अभियान की चर्चा करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचायत जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे गांव स्तर पर जनसहभागिता से सफाई अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दें, ताकि स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने जोल सप्टड में निर्माणधीन डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान मेडिकल कालेज और नए परिसर का निर्माण कर रही कंपनी के

अधिकारियों ने अनुराग सिंह ठाकुर को कालेज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिलासपुर में एस. ऊना में पीजीआई सेटलाइट सेंटर और हमीरपुर, चंबा तथा नाहन में नए मेडिकल कालेज बनने के बाद प्रदेशवासियों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के साथ संवाद किया तथा सराहनीय कार्य करने वाले कामगारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, एचआरटीसी उपाध्यक्ष विजय अग्रिहोत्री, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी, भाजपा के पदाधिकारी, डीसी देवशेता बनिक्, एसपी डॉ. आकृति शर्मा, मेडिकल कालेज की प्रधानाचार्य डॉ. सुमन यादव, मेडिकल कालेज अस्पताल के एमएस डॉ. रंजेश चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

असम में विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने घोषित किए तीन उम्मीदवार

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम विधानसभा की पांच सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार को तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पार्टी ने उन विधायकों को ही अपना उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने पिछला चुनाव जीतने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। मतगणना दो नवंबर को होगी। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य की भवानीपुर सीट से फणिधर तालुकदार, मारियानी से रूपज्योति कुर्मी और थोवारा से सुशांत बोरोहोहेन भाजपा के उम्मीदवार होंगे। कुर्मी और बोरोहोहेन ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जबकि तालुकदार ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के टिकट पर जीत दर्ज की थी। तीनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी दलों के विधायकों को भाजपा में शामिल करकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं। इसी प्रयास के तहत तीनों विपक्षी विधायकों को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। इन तीनों सीटों के अलावा राज्य के बीटीआर क्षेत्र के गोसाईगांव और तमुलपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। गोसाईगांव से मौजूदा विधायक मजेंद्र नारजारी और तमुलपुर से लेहो राम बोरो की कांविड-19 से मौत होने के कारण इन सीटों पर उप चुनाव कराया जा रहा है।

लखीमपुर की घटना पर भाकपा का विरोध, आईटीओ पर यातायात प्रभावित

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेताओं के एक समूह ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को कथित तौर पर मारे गए किसानों को अपना सम्भर्न देने के लिए सोमवार को दिल्ली में आईटीओ जंक्शन पर विरोध मार्च निकाला। भाकपा के वरिष्ठ नेता- पूर्व राज्यसभा सांसद डी. राजा और महसूचिव अतुल अंजान सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे आईटीओ जंक्शन पर धरने पर बैठ गए।

विरोध के चलते आईटीओ से प्रगति मैदान और मंडी हाउस तक वाहनों की आवाजाही करीब 30 मिनट तक ठप रही। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को राजा और अन्य भाकपा नेताओं से अनुरोध करते हुए देखा गया कि विरोध प्रदर्शन के कारण आईटीओ जंक्शन पर ट्रैफिक जाम हो गया। भाकपा नेताओं द्वारा जगह छोड़ने और यातायात की आवाजाही की

अनुमति देने से इनकार करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घोषणा करते हुए सुना, आईटीओ और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि वह जगह छोड़ दें और यातायात की आवाजाही की अनुमति दें। बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया, जिसके बाद आईटीओ जंक्शन पर यातायात फिर से शुरू हो सका।

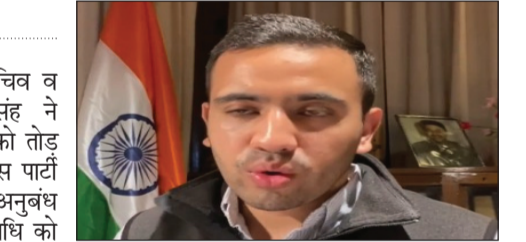
इस बीच, बात करते हुए अतुल अंजान ने कहा, रविवार को लखीमपुर खीरी में जो हुआ वह स्वीकार्य नहीं है। यह केंद्र द्वारा बनाए गए कटोर कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की हत्या का स्पष्ट मामला है। हम केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा भाजपा के आईटी सेल उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया , कांग्रेस पार्टी हमेशा से कर्मचारी हितैशी रही है

शिमला। (एजेंसी)।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा भाजपा के आईटी सेल उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा से कर्मचारी हितैशी रही है। अनुबंध कर्मचारियों के लिए अनुबंध का समय अवधि को कम करना हो या फिर एसएमसी, पैरा शिक्षक, पेट शिक्षकों के लिए नीति बनाने का काम हो यह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में हुआ है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को राहत दी है।

उनके बयान को भाजपा आईटी सेल द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा की ओच्छी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे वह इससे डरने वाले नहीं है। यह झूठ प्रोपोगेंडा मंहगाई, बेरोजगारी सहित जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के आम लोगों युवाओं, कर्मचारियों के साथ हैं और उनके हक को आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने



कहा कि बयान में यह कहा था कि कुछ चुनिंदा कर्मचारी भाजपा के पिंडू बने हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने कहा था कि जो चुनिंदा कर्मचारी भाजपा के पिंडू बने हुए हैं और राजनीतिक देश की भावना से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए होते हैं न कि राजनीति पार्टियों के लिए। दरअसल, एक जनसभा के मंच पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश के ऐसे कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक जो राजनीतिक देश की भावना से काम कर रहे हैं उन्हें पकड़-पटक कर दूसरे कोने में टांगसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कई कर्मचारी, अध्यापक और अधिकारी 20-20 का मैच खेल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यह सोचकर उनके नेताओं का गुणगान कर अपनी ट्रांसफर रकवाने में लगे हुए हैं।